(ङ) उक्त क्षेत्र में कोयले की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) शहडोल (मध्य प्रदेश) के निकट स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पट्टाधारी क्षेत्र में कोयले के भंडारों में से कोयले की चोरी होने की सूचना नहीं मिली है । जहां तक पट्टाधारी क्षेत्रों के बाहर कोयले की चोरी का संबंध है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Transportation and theft of coal in North Eastern coalfields

23. SHRI NYODEK YONGGAM : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) what is the total quantity and value of coal annually lost due to theft or other factors during transportation in North Eastern Coalfields at Ledo, Lekhapani, Tirap and Tipok coal mines under Coal India Ltd., and in Margherita, Assam; and

(b) what are the details of transporters registered with Coal India Ltd., Margherita, Assam ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) Quantity of coal lost in North Eastern Coalfields due to theft during transportation by road is Nil. Approximately 10,000 tonnes of coal amounting to about Rs. 60 lakhs were lost in 1992-93 during transhipment by railways from pitheads to transhipment point, for transfer from metre gauge to broad gauge wagons.

(b) No transporters are registered with North Eastern Coalfields, Margherita, Assam.

चाय पर वसूल किया गया उपकर

24. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित चाय की सभी किस्मों पर सरकार द्वारा उपकर वसूल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस उपकर की दर क्या है;

(ग) 1990-91, 1991 और 1992-93 के वर्षों के दौरान उपकर के रूप में कितनी राशि एकत्रित की गई;

(घ) उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि का प्रयोग करते हुए चाय की उत्पादकता में वृद्धि और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कोई योजना कार्यान्वित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है और उक्त प्रयोजन के लिए अब तक किस संस्था के माध्यम से इस राशि का उपयोग किया गया है; और

(छ) इस प्रकार से चाय उद्योग को कितना लाभ हो रहा है और उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अंतर्गत, उत्पादित की जाने वाली सभी प्रकार की चाय पर सरकार उपकर लगाती है । उपकर की वर्तमान दरें 3 पैसा प्रति कि. ग्रा. तथा 15 पैसे प्रति कि.ग्रा. हैं जो चाय उत्पादन के क्षेत्र पर निर्भर करती हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय पर वसूल उपकर निम्नलिखित रहा है :

वर्ष	वसूल उपकर की राशि (रुपए/लाख)
1990-91	1207
1991-92 (अनं.)	1234
1992-93 (अनं.)	1120

(घ) और (ङ) वसूल उपकर में से चाय बोर्ड को किए गए भुगतान का प्रयोग अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसंधान तथा विकास क्रिया-कलापों के लिए भी किया जाता है जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. चाय के छोटे उपजकर्ताओं को चाय की खेती के आधुनिक पहलुओं का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना;

2. कृषि तरीके अपनाने के प्रभाव को दर्शाने के लिए प्रदर्शन स्थलों की स्थापना;

3. अधिक उपज देने वाली किस्मों की रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए पौधशालाओं की स्थापना;

4. मुफ्त सलाह सेवाएं प्रदान करना;

5. अधिकतम उपज प्राप्त करने, नीलामी में अधिकतम कीमत प्राप्त करने, आदि के लिए पुरस्कार देना;

6. बड़े तथा छोटे दोनों चाय बागानों के लिए अनुसंधान तथा प्रसार सहायता।

(च) चाय बोर्ड के वित्तीयन अर्थात् उसके लिए धनराशि की व्यवस्था का उपकर ही मुख्य स्रोत है। चाय बोर्ड के कार्य हैं श्रम कल्याण उपायों के अलावा, उत्पादन, अनुसंधान तथा विकास कार्य और निर्यात संवर्धन के संबंध में चाय उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।

(छ) उपकर के रूप में वसूल धनराशि चाय उद्योग के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हुई है और यह बात अनुसंधान और विकास योजनाओं के जरिए उत्पादन बढ़ाने और विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के संवर्धन से पता चलती है।

Removal of restriction on imports

25. SHRI SUNIL BASU RAY : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the removal of severe restrictions on imports this year specially from non-essential items, has resulted in a significant trade gap which may cross rupees ten thousand Crores; and

(b) if so, what are the circumstances under which restrictions were removed;

(c) whether IMF aids have any influence in removing the import restrictions ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No Sir. Import of Non-essential items generally categorised as consumer goods, continue to be in the Negative List of Imports and therefore under restraint.

(b) and (c) Do not arise.

Non-Achievement of export target

26. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that exports during the period for April, 1992 to February, 1993 continue to remain far below the original export target of 12.8 per cent in dollar terms;

(b) whether exports to general currency areas have also declined during this period;

(c) if so, what are the facts in this regard and also the reasons therefor;

(d) what is the manner in which Government propose to achieve the growth target in exports during this year;

(e) whether the imports have also declined in February to 13.14 per cent as against 14.6 per cent during this period; and

(f) if so, what are the facts in this regard and the reasons for trade deficit as compared to the same period last year ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) In US dollar terms export during April-February 1992-93 have registered a growth of 2.81% over the corresponding period of 1991-92.